भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-6

उत्तर देने की तारीख-04/12/2023

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 द्वारा विद्यालयी और उच्च शिक्षा में सुधार

†*6. **श्री राहुल रमेश शेवाले:**
श्री चंद्र शेखर साहू:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 के तहत देश में, विशेषकर महाराष्ट्र में, तकनीकी शिक्षा सहित विद्यालयी शिक्षा और उच्च शिक्षा में विभिन्न सुधारों का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो विद्यालयी शिक्षा के साथ-साथ उच्च शिक्षा में उपर्युक्त सुधारों के कार्यान्वयन हेतु की गई कार्रवाई / प्रस्तावित कार्यकलापों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 तैयार करने से पहले उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में अखिल भारतीय सर्वेक्षण किया गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या इस सर्वेक्षण से देश में उच्च शिक्षा का सम्पूर्ण परिदृश्य सामने आया है;

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा देश में उच्च शिक्षा के सम्पूर्ण परिदृश्य की जानकारी लिए बिना राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तकनीकी शिक्षा सहित उच्च शिक्षा में कितना सुधार करने में सक्षम है?

उत्तर

शिक्षा मंत्री

(श्री धर्मेन्द्र प्रधान)

(क) से (च): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

"राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 द्वारा विद्यालयी और उच्च शिक्षा में सुधार" के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री राहुल रमेश शेवाले और श्री चंद्र शेखर साहू द्वारा दिनांक 04.12.2023 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 6 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और **(ख):** राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी 2020) में स्कूली शिक्षा के साथ-साथ तकनीकी शिक्षा सहित उच्च शिक्षा में कई सुधारों का प्रावधान है और इसमें पूरे देश में इसके कार्यान्वयन के लिए कई कार्य बिंदु/गतिविधियां निर्धारित की गई हैं। सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में कई पहल की हैं जैसे स्कूलों के उन्नयन के लिए पीएम श्री (पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया); कक्षा 3 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता सुनिश्चित करने के लिए समझ के साथ पढ़ने और संख्यात्मकता में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल (निपुण भारत); विद्या-प्रवेश - तीन महीने की प्ले-आधारित स्कूल की तैयारी मॉड्यूल के लिए दिशानिर्देश; शिक्षा के लिए सुसंगत मल्टी-मोड पहुंच को सक्षम बनाने के लिए डिजिटल/ऑनलाइन/ऑन-एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकत्र करने के लिए पीएम ई-विद्या, ई-बुक्स और ई-कंटेंट वाले वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में दीक्षा (ज्ञान साझा करने के लिए डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर), फाउंडेशनल स्टेज के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क (एनसीएफ एफएस) का आरंभ तथा 3 से 8 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए तैयार प्ले-आधारित शिक्षण अध्यापन सामग्री के लिए जादुई पिटारा; निष्ठा (स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल) 1.0, 2.0 और 3.0 शैक्षिक प्रबंधन में शिक्षकों, मुख्य शिक्षकों/ प्रधानाचार्यों और अन्य हितधारकों के लिए स्कूल शिक्षा के विभिन्न चरणों के लिए एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम; शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को सक्रिय और उत्प्रेरित करने के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय डिजिटल अवसंरचना का सृजन करने के लिए राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा संरचना (एनडीईएआर), 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी निरक्षरों को लक्षित करते हुए "न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम या यूएलएलएएस" योजना का कार्यान्वयन आदि।

इसी प्रकार, उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय ऋण क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ); राष्ट्रीय उच्च शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क (एनएचईक्यूएफ); स्नातक कार्यक्रम के लिए पाठ्यचर्या और क्रेडिट फ्रेमवर्क जैसे दिशानिर्देश/विनियम; शैक्षणिक कार्यक्रम में एकाधिक प्रवेश और निकास; उच्च शिक्षण संस्थानों (एचईआई) को बहु-विषयक संस्थानों में बदलना; एक साथ दो शैक्षणिक कार्यक्रमों में प्रवेश; अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट; ओडीएल/ऑनलाइन शिक्षा का संशोधित विनियमन; स्वयं मंच का उपयोग करके पाठ्यक्रमों के 40% तक क्रेडिट की अनुमति; ट्विनिंग, संयुक्त डिग्री और दोहरी डिग्री कार्यक्रम का प्रस्ताव करने के लिए भारतीय और विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों के बीच अकादमिक सहयोग पर विनियम; कॉलेजों को स्वायत्त दर्जा प्रदान करने पर विनियम; भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों में यूजी और पीजी में विदेश से आने वाले छात्रों के लिए प्रवेश और अतिरिक्त सीटों के लिए दिशानिर्देश, पीएचडी डिग्री प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानकों और प्रक्रियाओं पर विनियम; भारत में विदेशी उच्चतर शिक्षण संस्थानों के परिसरों की स्थापना और संचालन पर विनियमन; भारतीय भाषाओं में पाठ्यक्रमों की पेशकश, पाठ्य सामग्री/पुस्तकों का अनुवाद और जेईई, एनईईटी,

सीयूईटी जैसी प्रवेश परीक्षाएं; उद्योग-अकादमिक सहयोग और उद्यमिता पहल को बढ़ाने के लिए जैसे प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस पर दिशानिर्देश ताकि एचईआई उद्योग विशेषज्ञों के साथ काम करने में सक्षम हो सकें; प्रशिक्षुता/इंटर्नशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम की पेशकश करने के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए दिशानिर्देश; उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसंधान एवं विकास की स्थापना पर दिशानिर्देश; उद्योग की मांग को पूरा करने के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा उद्योग संरेखित पाठ्यक्रम जैसी विभिन्न पहल सुधार किए गए हैं। भारतीय ज्ञान के संवर्धन के लिए भारतीय ज्ञान प्रणाली (आईकेएस) पर संकाय के प्रशिक्षण/उन्मुखीकरण, उच्च शैक्षिक संस्थाओं में कारीगरों/कारीगरों को निवास के साथ सूचीबद्ध करने, भारतीय विरासत और संस्कृति पर आधारित पाठ्यक्रमों की शुरूआत, उच्चतर शिक्षा पाठ्यचर्या में भारतीय ज्ञान को शामिल करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

(ग) से (ङ): शिक्षा मंत्रालय देश में उच्चतर शिक्षा की स्थिति को दर्शाने के लिए वर्ष 2010-11 से उच्चतर शिक्षा पर वार्षिक वेब आधारित अखिल भारतीय सर्वेक्षण (एआईएसएचई) आयोजित करता है। सर्वेक्षण में देश के उन सभी संस्थानों को शामिल किया गया है जो उच्च शिक्षा प्रदान करने में लगे हुए हैं। शिक्षकों, छात्र नामांकन, कार्यक्रमों, परीक्षा परिणामों, शिक्षा वित्त, बुनियादी ढांचे जैसे कई मापदंडों पर डेटा एकत्र किया जा रहा है। शैक्षिक विकास के संकेतक जैसे संस्थान घनत्व, सकल नामांकन अनुपात, छात्र-शिक्षक अनुपात, जेंडर समानता सूचकांक, आदि शिक्षा क्षेत्र के विकास के लिए सूचित नीतिगत निर्णय लेने और अनुसंधान करने में उपयोगी हैं। जहां तक एनईपी 2020 का संबंध है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए डॉ. के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में गठित समिति ने एआईएसएचई वर्ष 2015-16 और वर्ष 2016-17 के संदर्भ सहित सुझावों, इनपुट, रिपोर्टों की एक विशाल मात्रा का विश्लेषण और जांच की थी।

(च): एनईपी 2020 की घोषणा के बाद से, उच्च और तकनीकी शिक्षा प्रणाली में कई सकारात्मक प्रभाव देखे गए हैं। अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) जो व्यापक आधार वाले बहु-विषयक/अंतर-अनुशासनात्मक, लचीले पाठ्यक्रम के साथ समग्र शिक्षा, विषयों के रचनात्मक संयोजन, कई माध्यम, समानता स्थापित करने, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता की सुविधा आदि के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) और राष्ट्रीय उच्च शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क को एक मंच प्रदान करता है, चालू है और विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है। अब तक 1655 विश्वविद्यालय/आईएनआई/उच्च शिक्षा संस्थान एबीसी पोर्टल पर हैं और 2.62 करोड़ छात्र पंजीकृत हैं। समानता और समावेश के साथ उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए भारतीय भाषाओं में पाठ्यक्रम पेश किए जा रहे हैं; जेईई, एनईईटी, सीयूटीईटी जैसी प्रवेश परीक्षाएं 13 भारतीय भाषाओं में आयोजित की जाती हैं; 12 भारतीय भाषाओं में विभिन्न विषयों पर यूजी छात्रों के लिए 100 किताबें लॉन्च की गईं है। प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, वर्तमान में, 95 उच्च शिक्षण संस्थान 1149 ओडीएल कार्यक्रमों का प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं और 66 उच्च शिक्षण संस्थान 371 ऑनलाइन कार्यक्रमों का प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। 19 लाख से अधिक छात्र इन सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। बहु-विषयक

शिक्षा को बढ़ावा देने और लचीलापन प्रदान करने के लिए लगभग 295 विश्वविद्यालयों ने स्वयं विनियमन को अपनाया है जो शिक्षार्थियों को स्वयं मंच से 40% तक क्रेडिट पाठ्यक्रमों का लाभ उठाने की अनुमति देता है। लगभग 9 लाख छात्र हर वर्ष स्वयं पर प्रमाणित हो रहे हैं। उद्योग और सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम विकसित करने में उद्योग विशेषज्ञों के साथ काम करने के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों को सक्षम बनाने के लिए, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस पर संबन्धित दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। 100 से अधिक उच्च शिक्षण संस्थान शिक्षुता/इंटर्नशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम प्रस्तुत कर रहे हैं। उच्च शिक्षण संस्थानों के प्रवेश से लेकर डिग्री प्रदान करने तक के लिए प्रौद्योगिकी सक्षम उद्यम संसाधन योजना (ईआरपी) आधारित समाधान (एसएएमटीएच) का 32 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कवर करते हुए लगभग 2700 विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है। 7 राज्य उच्चतर शिक्षा विभाग भी इसमें शामिल हैं। सिस्को/आईबीएम/मेटा/एडोब/माइक्रोसॉफ्ट/सेल्सफोर्स जैसी अग्रणी कंपनियों के साथ उद्योग-संरेखित पाठ्यक्रम बनाने के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। उद्योग की मांग को पूरा करने के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा पाठ्यक्रम भी शुरू किए गए हैं। इंटर्नशिप के लिए एकल एकीकृत ऑनलाइन पोर्टल निर्धारित किया गया है और लगभग 10560 एचईआई और 71883 उद्योग पोर्टल पर पंजीकृत हैं। वर्तमान में, लगभग 7550 संस्थानों की नवाचार परिषदों की स्थापना की गई है। लगभग 104 उच्च शिक्षण संस्थानों को विचार विकास, मूल्यांकन और अनुप्रयोग प्रयोगशालाओं (आईडीईए) के लिए वित्त पोषित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देने के लिए जांजीबार, तंजानिया में आईआईटी मद्रास और अबू धाबी में आईआईटी, दिल्ली परिसर स्थापित किए गए हैं। कई पहलों के माध्यम से भारतीय ज्ञान को बढ़ावा देने का उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण आदि के क्षेत्र में भारत की भविष्य की आकांक्षाओं की स्पष्ट भावना के साथ प्राचीन भारत के ज्ञान, आधुनिक भारत में इसके योगदान को इसकी सफलताओं में शामिल करना और चुनौतियों का समाधान करना है। वर्तमान में कई पहल, जैसे कि आईकेएस के मूल अनुसंधान, शिक्षा और प्रसार को उत्प्रेरित करने के लिए 53 आईकेएस केंद्रों की स्थापना, 88 अनुसंधान परियोजनाएं जैसे प्राचीन धातु विज्ञान, प्राचीन नगर नियोजन और जल संसाधन प्रबंधन, प्राचीन रसायन शास्त्र आदि जैसी अंतर-अनुशासनात्मक अनुसंधान परियोजनाएं और पाठ्यक्रम में आईकेएस को अपनाना आदि की गई हैं ।

*****